नईदुनिया

एलजीबीटी क्लब के दरवाजे पर अमेरिकी अधिकारी ने पहले पेशाब फिर कर्मियों से की मारपीट; विवाद बढ़ा तो दिया इस्तीफा

वॉशिंगटन ।

दुनियाभर में एलजीबीटी समुदाय के लोग अपने-अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी यह सामान्य लोगों की तरह जिंदगी नहीं बिता पा रहे हैं। इस बीच, अमेरिका में एलजीबीटी समुदाय के क्लब से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है।दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को एलजीबीटी के नाइट क्लब के दरवाजे पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में कथित तौर पर दक्षिण कैलिफोर्निया के काउंसिल सदस्य क्रिस किलपैट्रिक को लॉस एंजिल्स में एक एलजीबीटी नाइट क्लब के दरवाजे पर पेशाब करते हुए और फिर क्लब के प्रबंधक के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए क्रिस ने इस्तीफा दे दिया है।

नाइट क्लब ने वीडियो साझा किया

इस वीडियो को नाइट क्लब प्रीसिंक्ट ने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इसमें देखा जा सकता है कि क्लब के दरवाजे पर दो लोग आए और पेशाब करने लगे। प्रीसिंक्ट ने एलजीबीटी समुदाय के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया और दोनों पुरुषों की निंदा की।

कर्मचारी को जमीन पर धकेला

क्लब ने कहा, दो लड़के बार में आए। इन दो लोगों ने सभी को यह दिखाने का फैसला किया कि प्रीसिंक्ट में क्या नहीं करना है। वह पहले शराब से भरे ग्लास को लेकर बाहर गए। उसके बाद कर्मचारियों के प्रवेश करने वाले दरवाजे पर पेशाब की। जब एक कर्मचारी ने यह सब देखा तो उनसे ग्लास लेने की कोशिश की। लेकिन इनमें से एक ने कर्मचारी को पीट दिया और उसे जमीन पर धकेल दिया। क्लब सबके लिए सुरक्षित है। यहां अच्छा समय बिताएं, यह सब न करें। हमारे यहा बाथरूम है।

अधिकारी के वकील का तर्क

हालांकि, क्रिस किलपैट्रिक के वकील ने घटना को अलग तरीके से बताया है। उनका दावा है कि क्लब के कर्मचारी उनपर आक्रामक हो रहे थे, वह अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे। वकील ने तर्क दिया कि किलपैट्रिक की हरकतें सही थीं और सार्वजनिक पेशाब करना उल्लंघन था, वो भी मामूली। विवाद को बढ़ता देख किलपैट्रिक ने सुनवाई से ठीक एक दिन पहले टाउन काउंसिल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं, काउंसिल पहले ही कह चुकी थी कि अगर आरोप सही साबित हुए तो किलपैट्रिक को हटा दिया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होते हुए गुम हुआ स्टारशिप, मस्क बोले- ये मानवता को मंगल पर लेकर जाएगा

वॉशिंगटन । दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल स्पेसएक्स के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का तीसरा परीक्षण लगभग सफल रहा। हालांकि परीक्षण के दौरान स्टारशिप जब अंतरिक्ष की उड़ान भरने के बाद वापस पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो रहा था, उस दौरान स्टारशिप का संपर्क टूट गया। परीक्षण की सफलता पर एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्टारशिप,मानवता को मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा। पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होते हुए टूटा संपर्क स्पेसएक्स के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप ने टेक्सास स्थित कंपनी के स्टारबेस बोका चिका से सुबह स्थानीय समय अनुसार, करीब 8.25 बजे उड़ान भरी। इस उड़ान का लाइव वेबकास्ट भी किया गया, जिसे सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने देखा। परीक्षण के दौरान सबकुछ ठीक रहा, सिर्फ पृथ्वी के वातावरण में फिर से एंट्री के दौरान रॉकेट से कंट्रोल रूम का संपर्क टूट गया। यह संपर्क उस वक्त टूटा, जब स्टारशिप हिंद महासागर के ऊपर था। हालांकि रॉकेट समुद्र में लैंड करने में सफल रहा। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप स्पेसएक्स का रॉकेट स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जिसकी लंबाई 397 फीट है और इसमें सुपर हैवी बूस्टर लगे हैं, जो 16.7 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट पैदा करते हैं। नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर रॉकेट हैं, लेकिन यह भी स्टारशिप की तुलना में आधा ही थ्रस्ट पैदा करता है। हालांकि स्टारशिप अभी प्रोटोटाइप स्टेज में ही है और नासा का रॉकेट सर्टिफाइड है और संचालन में है। तीसरे परीक्षण में स्टारशिप ने अपने अधिकतर उद्देश्यों को पूरा किया और कंपनी ने भी इस पर खुशी जताते हुए परीक्षण को करीब-करीब सफल बताया है। स्टारशिप रॉकेट रीयूजेबल है और यह अंतरिक्ष में 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप में 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाया जा सकेगा। स्टारशिप रॉकेट का पहला परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया था, लेकिन उस दौरान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद स्टारशिप धमाके के साथ तबाह हो गया था। स्टारशिप का दूसरा परीक्षण नवंबर 2023 में किया गया। हालांकि अंतरिक्ष में जाने के बाद दूसरे परीक्षण में भी रॉकेट तबाह हो गया था। पहले दो परीक्षणों की तुलना में स्टारशिप का तीसरा परीक्षण काफी सफल रहा है। स्टारशिप का यह परीक्षण इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दशक के अंत में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा स्टारशिप रॉकेट की मदद से ही अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की योजना बना रही है।

क्या चीन और रूस से सैटेलाइट के जरिए अमेरिका में फोन को मिल रहे सिग्नल! एफसीसी ने बिठाई जांच

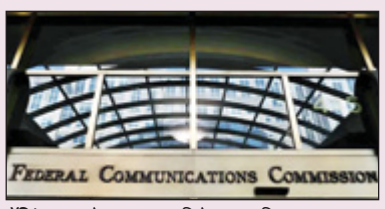

वॉशिंगटन । फेडरल कम्यूनिकेशन कमिशन (एफसीसी) ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अमेरिका में मोबाइल जैसे उपकरण, विदेशी विरोधियों रूस और चीन द्वारा नियंत्रित सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त कर रहे और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एफएसएसी ने चिंता जाहिर की है कि मोबाइल फोन जैसे उपकरण विदेशी विरोधियों द्वारा नियंत्रित सैटेलाइट से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं, जो आयोग के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह अभ्यास सुरक्षा खतरा पैदा करता है या नहीं। जांच चल रही है एफसीसी ने जांच का खुलासा किया और कहा कि जांच चल रही है। वहीं, एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी कई महीने पहले शुरू हुई जांच में एप्पल इंक, अल्फाबेट इंक के गूगल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और नोकिया ओयज सहित डिवाइस निर्माताओं की जांच कर रही है। एप्पल, गूगल, मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग और अन्य से जवाब मांग जा रहा है। फिलहाल इन कंपनियों ने कोई बयान जारी नहीं किया है। एफसीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, फिलहाल कोई सबूत नहीं है कि सुरक्षा में उल्लंघन हुआ है या नहीं। चीन ने की थी अमेरिका से बात हाउस सेलेक्ट चाइना कमेटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि माइक गैलाघेर ने इस सप्ताह की शुरुआत में एफसीसी अध्यक्ष जेसिका रोसेनवोर्सेल से बात की और उन रिपोर्टों के बारे में चिंता जताई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेल फोन चीनी और रूसी उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त कर रहे थे और इस्तेमाल किए जा रहे थे।

हाईकोर्ट से इमरान समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लगा झटका, अब खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

इस्लामाबाद ।

इमरान खान की पार्टी ने घोषणा की है कि वह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की याचिका को खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें अन्य दलों को आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पाकिस्तान में आठ फरवरी को हुए आम चुनावों के बाद से सियासी उठा पटक जारी है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा था, जिसका फायदा पूर्व पीएम नवाज शरीफ को मिला। दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने खान समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को आरक्षित सीटें देने से मना कर दिया था, जिससे नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल-एन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। इसके बाद एसआईसी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, हालांकि वहां से भी उसे मायूस लौटना पड़ा। अब इमरान खान की पार्टी ने एलान कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इस समय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।

हाईकोर्ट से झटका - पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने खान समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को झटका देते हुए उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने लगातार दो दिनों तक दलीलें सुनीं और एसआईसी द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस याचिका में पीटीआई के सांसदों ने आठ फरवरी के चुनावों के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के अपने हिस्से का दावा किया था। इस फैसले के बाद पीटीआई के अध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी आरक्षित सीटों के अपने हिस्से का दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। गौहर ने शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने का आग्रह किया।

चुनाव कानून की धारा 104 को भी चुनौती दी - एसआईसी ने अदालत से पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को संसद में उनकी संख्या के आधार पर आरक्षित सीटें आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में चुनाव कानून की धारा 104 को भी चुनौती दी गई थी

जो आरक्षित सीटों के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से संबंधित है।

अदालत ने छह मार्च को एसआईसी को अंतरिम राहत दी थी और नेशनल असेंबली के स्पीकर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आरक्षित सीटों पर चुने गए आठ सांसदों को शपथ नहीं दिलाने का निर्देश दिया था। इस मामले में जटिल कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए, पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने एक विशेष बड़ी पीठ का गठन किया था, जिसमें न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम, न्यायमूर्ति एजाज अनवर, न्यायमूर्ति सैयद मुहम्मद अतीक शाह, न्यायमूर्ति शकील अहमद और न्यायमूर्ति सैयद अरशद अली शामिल थे।

एसआईसी को आरक्षित सीटें देने से किया था इनकार - पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने हाल ही में 71 साल के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) समर्थित सुन्नी इतेहाद काउंसिल (एसआईसी) को आरक्षित सीटें देने से इनकार कर दिया था। आयोग का कहना था कि एसआईसी के पाले वालीं आरक्षित सीटें अन्य दलों को दे दी जाएं।

दरअसल, पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें अपने नाम की थीं, लेकिन वे बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए थे। इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएलएन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने घोषणा कर दी थी कि वे गठबंधन सरकार बनाएंगे। हालांकि, पीटीआई ने पीएमएलएन और पीपीपी द्वारा गठबंधन सरकार बनाने के प्रयासों को खारिज कर दिया था।

किस पार्टी ने कितनी जीती थीं सीटें - चुनावों में जेल में बंद इमरान खान की पीटीआई पार्टी की ओर से समर्थित उम्मीदवारों समेत कुल 93 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नेशनल असेंबली की सीटें जीती थीं। पीएमएल-एन ने 75 सीटें जीतीं, जबकि पीपीपी 54 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने भी 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहां सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 266 सदस्यीय नेशनल असेंबली में लड़ी गई 265 सीटों में से 133 सीटें चाहिए होंगी। कुल मिलाकर, संसद के निचले सदन की 336 सीटों में से 266 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अन्य 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित थीं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने पिछले महीने हुए आम चुनाव के बाद शुरुआत में 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसमें नौ निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसे महिलाओं के लिए 19 आरक्षित सीटें और अल्पसंख्यकों के लिए चार आरक्षित सीटें आवंटित की गईं, जिससे इसकी कुल संख्या 107 हो गई थी।

पीटीआई समर्थित अंतरिम सुरक्षा परिषद (आईएससी) को आरक्षित सीटें देने से ईसीपी के इनकार के बाद तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ नीत पीएमएल-एन को महिलाओं के लिए आरक्षित 20 सीटों में से 15 सीटें और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित तीन सीटों में से एक सीट आवंटित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 123 सीट के साथ नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) को मिली सीटों की संख्या भी पहले की 68 सीटों से बढ़कर 73 हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी के नेतृत्व वाली पार्टी ने शुरू में 54 सामान्य सीटें जीतीं और उसे अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 12 सीटें और महिलाओं के लिए दो सीटें आवंटित की गईं। इसके बाद इसे महिलाओं के लिए आरक्षित चार और अल्पसंख्यकों के लिए एक सीट आवंटित की गई थी।

मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) पार्टी के नेशनल असेंबली में 22 सदस्य हैं जबकि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) के सांसदों की संख्या सात से बढ़कर 11 हो गई है।

युद्ध के बीच मोहम्मद मुस्तफा फलस्तीन के नए पीएम नियुक्त, वेस्ट बैंक में सरकार का करेंगे नेतृत्व

यरुशलम ।

फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फलस्तीनी प्राधिकरण (पीए) में सुधार को लेकर अमेरिकी दबाव के बीच मोहम्मद मुस्तफा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मुस्तफा लंबे समय से अब्बास के आर्थिक सलाहकार रहे हैं। गाजा युद्ध के मद्देनजर फलस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति अमेरिका की पोस्ट-वॉर योजना का हिस्सा बताई जा रही है। फलस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह ने पिछले महीने सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति अब्बास ने एक बयान में प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफा की नियुक्त की जानकारी दी। साथ ही अब्बास ने नए पीएम से वेस्ट बैंक और गाजा में प्रशासन को फिर से एकीकृत करने, सरकार, सुरक्षा सेवाओं और अर्थव्यवस्था में सुधारों का नेतृत्व करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए योजनाएं बनाने को कहा। अमेरिका से शिक्षित अर्थशास्त्री मोहम्मद मुस्तफा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तकनीकी सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो गाजा को देश का दर्जा देने से पहले प्रशासित कर सकती है। मुस्तफा को राजनीतिक रूप से खुले विचार का माना जाता है। हालांकि, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध के बाद की अमेरिका की योजनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में नई सरकार की नियुक्ति अमेरिकी सुधार की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि 88 वर्षीय राष्ट्रपति अब्बास का फलस्तीनी प्राधिकरण पर पूरा नियंत्रण रहेगा। फलस्तीनी नागरिक राजनीति में बदलाव चाहते हैं, नामों में नहीं फलस्तीनी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और क्षेत्र के देश जो बदलाव चाहते हैं, जरूरी नहीं कि फलस्तीनी नागरिक भी वही बदलाव चाहते हों। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी नागरिक सही मायने में राजनीति में बदलाव चाहते हैं, नामों में नहीं। वे चुनाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तफा एक सम्मानित और शिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन क्या वह वेस्ट बैंक के हालात में सुधार के लिए लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे।

बस, अब बहुत हुआ, अभिनेता बाल्डविन ने अपने खिलाफ लगे हत्या के आरोपों को खारिज करने की मांग की

नई दिल्ली ।

फिल्म अभिनेता एलेक बाल्डविन ने फिल्म शूटिंग के दौरान अपने ऊपर लगे हत्या के आरोपों को खारिज करने की मांग की है। बाल्डविन के वकील ने न्यू मैक्सिको की एक कोर्ट से अपील की है। साल 2021 में फिल्म रस्ट की शूटिंग के दौरान चली गोली से फिल्म की सिनेमैटोग्राफर हेलिना हचिन्स की मौत हो गई थी। इस मामले में क्रू मेंबर ने फिल्म के अभिनेता और निर्माता एलेक बाल्डविन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

एलेक बाल्डविन पर गैर इरादतन हत्या के साथ ही हथियारों के साथ लापरवाही बरतने का भी आरोप है। माना जा रहा है कि जुलाई से बाल्डविन के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है।

बाल्डविन के वकीलों ने दी ये दलीलें

बाल्डविन के वकील ने कोर्ट में कहा कि अब बस बहुत हो गया है। यह व्यवस्था द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न है। साथ ही यह निर्दोष नागरिक के अधिकारों का भी उत्पीड़न है। बाल्डविन की याचिका में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभी तक एक भी गवाह को गवाही के लिए नहीं बुलाया है। याचिका में कहा गया है कि बाल्डविन फिल्म से बतौर क्रिएटिव निर्माता जुड़े हुए हैं और फिल्म सेट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

क्या है मामला

साल 2021 में 21 अक्तूबर को न्यू मैक्सिको में फिल्म रस्ट की शूटिंग के दौरान एलेक बाल्डविन की प्रॉप गन से गोली चली थी। जिससे सिनेमैटोग्राफर हलिना हचिन्स की मौत हो गई थी और फिल्म के निर्देशक जोएल डिसूजा घायल हो गए थे। बाल्डविन का दावा है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई और प्रॉप गन में नकली गोलियां होनी चाहिए, लेकिन उसमें असली गोलियां भरी हुई थी। वहीं बाल्डविन के खिलाफ मुकदमा करने वाले क्रू मेंबर का दावा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर होने के नाते बाल्डविन को ध्यान रखना चाहिए था कि प्रॉप गन एक हथियार है। क्रू मेंबर ने बाल्डविन पर लापरवाही से प्रॉप गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान: 94 हजार केंद्रों पर तीन दिन चलेगी वोटिंग, पुतिन का पांचवीं बार जीतना तय

मॉस्को ।

यूक्रेन से जंग के बीच रूस में आज से आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई हैं। रूस में 15 से 17 मार्च तक मतदान चलेंगे। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। उम्मीद है कि वे पुतिन पांचवी बार सत्ता में लौटेंगे। पांचवी बार उनका सत्ता में आना लगभग निश्चित है। रूसी मीडिया रिपोर्ट की मानें तो, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों जैसे पूर्वी कामचटका और चुकोटका में मतदान केंद्र पहले ही खुल गए थे। कामचटका के राज्यपाल व्लादिमीर सोलोडोव ने क्षेत्र में सबसे पहले वोटिंग की। वहीं, डोनबास और नोवोरोसिया में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। दोनों क्षेत्रों के लोग पहली बार अपने राष्ट्रपति का चयन करेंगे। बता दें, डोनबास और नोवोरोसिया यूक्रेनी शहर हैं, जिस पर अब रूस का कब्जा है।

94 हजार से अधिक मतदान केंद्र 12 घंटे खुले रहेंगे - चुनाव आयोग की अध्यक्ष एला पामफिलोवा ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि रूस में तीन दिनों तक मतदान हो रहे हैं और लोगों को यह पहल पसंद आई है क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए अधिक समय मिल रहा है। रूस के 94,000 से अधिक मतदान केंद्र सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। मतदान औपचारिक रूप से 17 मार्च को रात 9 बजे (स्थानीय समय) खत्म हो जाएंगे। लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने का भी विकल्प है। मॉस्को सहित 29 अलग-अलग क्षेत्रों में ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। 4.7 मिलियन से अधिक लोगों ने ऑनलाइन वोट करने के लिए आवेदन किया है।

दूसरे दौर का मौका भी मिलेगा - हालांकि, प्रारंभिक और डाक मतदान पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें यूक्रेन का कुछ हिस्सा भी शामिल हैं। यदि किसी उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट नहीं मिले पाए तो तीन सप्ताह बाद दूसरे दौर का मतदान होगा। अगर पुतिन दोबारा राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतते हैं तो वह करीब 2030 तक सत्ता पर बने रहेंगे।

रूस में पुतिन की लोकप्रियता सबसे अधिक - मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक गैर-सरकारी मतदान संगठन, लेवाडा सेंटर की एक रिपोर्ट की मानें तो पुतिन की रेटिंग 86 प्रतिशत से अधिक है। युद्ध के दौरान उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। मॉस्को की तात्याना का कहना है कि मैं पुतिन को वोट दे रही हूं। मुझे पुतिन पर भरोसा है। वह बहुत शिक्षित हैं। पुतिन वैश्विक नेता हैं। मैं पुतिन के नेतृत्व का समर्थन करती हूं।

यह हैं राष्ट्रपति पद के दावेदर

- निवर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
- व्लादिस्लाव दावानकोव
- लियोनिद स्लटस्की
- निकोले खारितोनोव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए शुरुआत में 33 लोगों ने दावेदारी की थी लेकिन 15 लोग ही आवश्यक दस्तावेज जमा कर पाए। हालांकि, एक जनवरी को दस्तावेज जमा करने की अंतिम समय सीमा तक 11 उम्मीदवार ही राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए बचे।

आगामी वर्षों में गेमचेंजर साबित होगा भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग, भारतवंशी रिचर्ड वर्मा का बड़ा दावा

वॉशिंगटन ।

भारत और अमेरिका का सुरक्षा सहयोग आने वाले वर्षों में बेहद अहम साबित होगा। ये दावा किया है कि शीर्ष अमेरिकी अधिकारी रिचर्ड वर्मा ने। वर्मा ने हाल ही में भारत का दौरा किया और अब एक ब्लॉग में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं पर बात की और दावा किया कि दोनों देशों का सहयोग वैश्विक स्तर पर गेमचेंजर साबित हो सकता है। रिचर्ड वर्मा ने जो बाइडन के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें बाइडन ने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। भारतवंशी रिचर्ड वर्मा ने बताया दोनों देशों में सहयोग की अपार संभावनाएं भारतवंशी रिचर्ड वर्मा, अमेरिका के विदेश विभाग में मैनेजमेंट एंड रिसोर्स विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पद पर तैनात हैं और वह भारत में

बतौर अमेरिका के राजनयिक भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रिचर्ड वर्मा ने अपने ब्लॉग में लिखा कि जैसा कि जो बाइडन और पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका का एक दूसरे पर पड़ने वाला असर बेहद अहम है, लेकिन हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, यह ज्यादा अहम है। खाद्य सुरक्षा, महामारी से निपटना और डिजिटल अर्थव्यवस्था ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दोनों देश बहुत कुछ कर सकते हैं।

इन तीन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे भारत-अमेरिका

वर्मा के अनुसार, रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य और तकनीक, ऐसे तीन अहम क्षेत्र हैं, जहां दोनों देशों में सहयोग अहम है और बीते कुछ दशकों में दोनों देशों के संबंधों के विकास में काफी प्रगति भी हुई है। रिचर्ड वर्मा ने लिखा कि आज जो हम खतरे देख रहे हैं, वो असल में हैं, लेकिन साथ मिलकर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। जानकारियों का आदान-प्रदान बढ़ा सकते हैं और समुद्री सीमाओं की रक्षा और जागरुकता बढ़ा सकते हैं। पूरे हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा में भारत की भूमिका खास रहेगी। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इमर्जिंग तकनीक में भी दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। इससे साइबर हमलों और इसके खतरों से निपटा जा सकेगा। डाटा सुरक्षा की दिशा में भी दोनों देशों को काम करना चाहिए। इसके लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और साइबर सिक्योरिटी साझेदारी कर दोनों देश इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही सेमीकंडक्टर से लेकर दुर्लभ खनिजों, अंतरिक्ष खोज, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में भी काफी संभावनाएं हैं।

अमेरिका ने कहा- हम सीएए लागू होने से चिंतित

अमेरिका की सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि वह भारत में सीएए लागू होने से चिंतित हैं और करीब से हालात पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च को सीएए लागू होने को लेकर चिंतित हैं और यह देख रहे हैं कि कैसे यह कानून लागू किया जाता है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रित सिद्धांत है। भारत सरकार ने नागरिकता संसोधन कानून 2019 को हाल ही में देश में लागू कर दिया है। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। मुस्लिमों को इस कानून से बाहर रखा गया है, जिसका विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है और इसमें किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है।